VISION IAS

www.visionias.in

VISION IAS
M N 24 AUG 2024 No. 3
RECEIVED

GENERAL STUDIES (TEST CODE : 2364)

Name of Candidate	Arun Kumar		
Medium Eng./Hindi	Hindi	Registration Number	1445517
Center	MN, Delhi	Date	24/08/2024

INDEX TABLE

Q. No.	Maximum Marks	Marks Obtained
1	10	
2	10	
3	10	
4	10	
5	10	
6	10	
7	10	
8	10	
9	10	
10	10	
11	15	
12	15	
13	15	
14	15	
15	15	
16	15	
17	15	
18	15	
19	15	
20	15	

Total Marks Obtained:

Remarks:

INSTRUCTIONS

1. Do furnish the appropriate details in the answer sheet (viz. Name, Registration Number and Test Code).
   उत्तर पुस्तिका में सूचनाएं भरना आवश्यक है (नाम, प्रश्न–पत्र कोड, विद्यार्थी क्रमांक आदि)।
2. There are **TWENTY** questions printed in **HINDI & ENGLISH.**
   इसमें बीस प्रश्न हैं **हिन्दी और अंग्रेजी** में छपे हैं।
3. **All questions are compulsory.**
   सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
4. The number of marks carried by a question/part is indicated against it.
   प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं।
5. Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other that the authorized one.
   प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है और उस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न–सह–उत्तर (क्यूसीए) पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिए गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
6. Word limit in questions, if specified, should be adhered to.
   प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए।
7. Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum-Answer Booklet must be clearly struck off.
   उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।

Is student recommended for One-to-One mentoring?

Recommended	Strongly Recommended

EVALUATION INDICATORS

1. Contextual Competence
2. Content Competence
3. Language Competence
4. Introduction Competence
5. Structure - Presentation Competence
6. Conclusion Competence

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

All the Best

For one-to-one mentoring session on this copy, call us at 7042691891 or send an email to appointment@visionias.in

2364

VISION IAS™

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

Q1. धन शोधन और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन के अपराधों की जांच करने के अपने अधिदेश को पूरा करने में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा सामना की जाने वाली आलोचनाओं पर चर्चा कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

Discuss the criticisms faced by the Enforcement Directorate (ED) in fulfilling its mandate of investigating offences of money laundering and violations of foreign exchange laws. (Answer in 150 words) 10

सुप्रीम कोर्ट ने धनशोधन के मामलों में ED तथा अन्य प्रवर्तनकारी एजेंसियों की प्रभाविता सुधारने हेतु उन्हें अपने प्रोफेशनल अधिदेश की पूर्ति करने की सलाह दी है बजाय के राजनीतिक तोता ।

ED का अधिदेश
- धन शोधन अपराधों को रोकना व जांच करना
- अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय लेन देन की जांच करते हुए प्रक्रियाओं को स्वच्छ बनाना
- भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना
- आतंकी वित्तपोषण रोकने हेतु FATF के साथ कार्य करना

ED की आलोचना :-

1) प्रवर्तन निदेशालय को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार vs ED वाद में अपने संवैधानिक अधिदेश की पूर्ति का निर्देश दिया ।

2). कुछ जानकारों ने ED की कार्यवाहियों को राजनीति से प्रेरित बताया है
(उदा०. विपक्षी नेताओं पर रेड डालना
→ चुनावों के दौरान नेताओं को धमकाना तथा सत्ताधारी पार्टी ज्वाइन करने के बाद उनसे संबंधित मुद्दे तथा फाइलें बंद कर देना।)

3). कार्यवाही में तरफदारी व अपारदर्शिता
(उदा० FEMA एक्ट के तहत अवैध गिरफ्तारियां)

4). गिरफ्तारियों व conviction rate में अंतर
(उदा० सिर्फ 4% लोगों पर ही दोषसिद्धी)

ED द्वारा की गई कार्यवाही
→ FATF के साथ मिलकर आतंकी वित्तपोषण को रोकना
→ अवैध खिलाड़ियों तथा रियल खिलाड़ियों की वित्तीय अनियमितताओं पर लगाम
→ चुनावों के दौरान कालाधन की जब्ती कर, धनबल को रोकना

अतः ED देश में वित्तीय तंत्र के अपराधों से निपटने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण है, ED को बिना राजनैतिक हस्तक्षेप के अपने संवैधानिक दायित्वों को निभाना चाहिए

Q2. विभागों से संबद्ध स्थायी समितियां (DRSCs), जिन्हें 'मिनी पार्लियामेंट' भी कहा जाता है, अपने कार्यों को करने में प्रभावी क्यों नहीं रही हैं? (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

Why are the Departmentally Related Standing Committees (DRSCs), also known as 'Mini Parliament', not effective in carrying out their functions? (Answer in 150 words) 10

संसदीय समितियां 'लघु संसद' के रूप में कार्य करती है। ये अपनी विशेषज्ञ सलाह व जांच से व्यापक विश्लेषण प्रदान करती है

संसदीय समितियां
- तदर्थ (Adhoc)
- स्थायी समितियां

- स्थायी समितियों का गठन 1 वर्ष के लिए किया जाता है। ये कार्य विशिष्ट होते हैं। इनके कार्य संपन्न होने पर इनको समाप्त कर दिया जाता है

विभागीय स्थायी समितिय
- आर्थिक मामलों की समिति
- कृषि संबन्धी समिति
- मानवाधिकार संबन्धी
- महिला व बाल विकास संबंधित
- श्रम कल्याण समिति
- पर्यावरण संबन्धी समिति
- नियम संचालन संबंधी संसदीय समिति

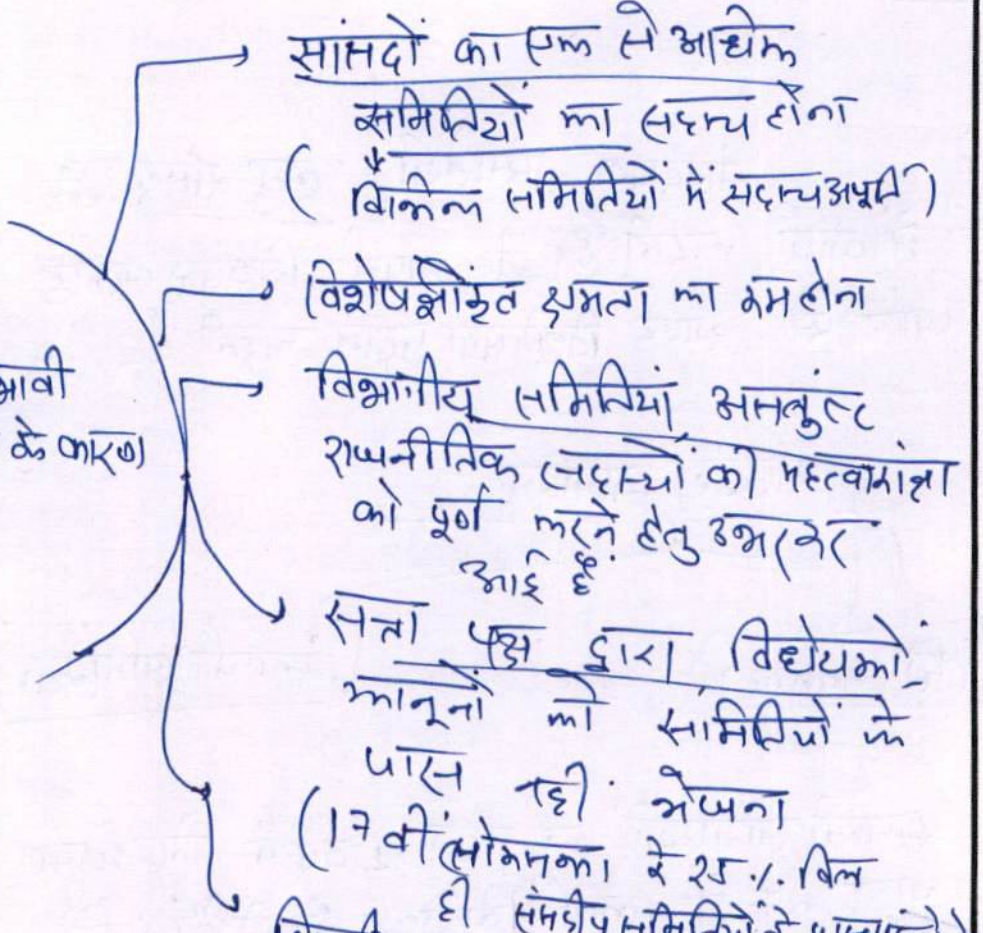

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

कम प्रभावी रहने के कारण

- सांसदों का एक से अधिक समितियों का सदस्य होना (विभिन्न समितियों में सदस्यअवधि)
- विशेषज्ञीकृत क्षमता का कम होना
- विभागीय समितियां अनुकूल राजनीतिक सदस्यों की महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने हेतु उभर रहे आई हैं
- सत्ता पक्ष द्वारा विधेयकों, कानूनों को समितियों के पास नहीं भेजना (17वीं लोकसभा में 25% बिल ही संसदीय समितियों के पास पहुंचे)
- विपक्षी सांसदों का कम प्रतिनिधित्व

प्रभावी बनाने के उपाय

- विधेयकों को समितियों के पास भेजना
- क्षमता निर्माण हेतु सदस्यों को प्रारंभिक प्रशिक्षण
- समितियों में सदस्यों की निश्चितता बढ़ाना, विशेषज्ञ दृष्टिकोण प्राप्त करना

अतः संसदीय कानूनों में समग्रता तथा जांच अन्वेषण विशेषज्ञता लाने हेतु विभागीय समितियां महत्वपूर्ण हैं इन्हें प्रभावी बनाया जाना चाहिए।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Q3. भारत, अमेरिका और ब्रिटेन में शक्ति पृथक्करण के संदर्भ में क्या समानताएं और भिन्नताएं हैं? (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

What are the similarities and differences with regard to the separation of powers in India, USA, and UK? (Answer in 150 words) 10

फ्रांसिसी विद्वान मान्टेस्क्यू तथा जॉन लॉक ने शक्ति संतुलन हेतु, तथा प्रभावी सुशासन हेतु शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की वकालत की। दुनियाभर में इन सिद्धांतों को अपनी जरूरतों के अनुसार अपनाया गया है।

समानताएं –

भारत	अमेरिका	ब्रिटेन
1) प्रभावी संतुलन हेतु कार्यपालिका, विधायिका न्यायपालिका में शक्ति विभाजन	शासन के तीनों अंगों के बीच स्पष्ट विभाजन	हाउस ऑफ लार्ड्स, हाउस ऑफ कामन्स तथा उच्चतम न्यायपालिका में शक्ति सीमांकन
2) लिखित संविधान द्वारा शक्तियों को परिभाषित करना	लिखित संविधान द्वारा शक्तियों को परिभाषित करना	अलिखित संविधान - संसदीय परम्पराओं व कानूनों द्वारा शक्ति विभाजन

भिन्नताएँ :-

भारत	अमेरिका	ब्रिटेन
1) शक्ति संतुलन पर जोर	स्पष्ट व कठोर शक्ति पृथक्करण	अलिखित संविधान से चलते शक्ति पृथक्करण कमजोर - प्रारम्भ में न्यायपालिका का प्रावधान नहीं (2005) से केंद्रीय न्यायपालिका जो कि हाउस ऑफ लार्ड्स व कॉमन्स के अधीन
2) शासन के अंगों कार्य०, विधायिका, न्यायपालिका के बीच समन्वय	संतुलन की व्यापक स्पष्ट सीमांकन	
3). संविधानवाद	संविधानवाद	संसद सम्प्रभुता

अतः भारत तथा अमेरिका में लिखित संविधान ने शासन सत्ता में संतुलन बनाने का प्रयास किया है वहीं ब्रिटेन में संसदीय सम्प्रभुता ने शक्ति पृथक्करण को कमजोर किया है। ~~अ~~ फलत: प्रभावी सुशासन हेतु शक्ति संतुलन आवश्यक है।

Q4. यद्यपि केंद्र सरकार द्वारा अपनाए गए उपायों ने राज्य की वित्तीय स्थिति को प्रभावित किया है, तथापि राज्य सरकारें स्वयं ही अपने समक्ष आने वाली वित्तीय चुनौतियों के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। विवेचना कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

Though measures adopted by the Central government have impacted state finances, the state governments themselves are mainly responsible for the financial challenges they face. Discuss. (Answer in 150 words) 10

संविधान के भाग XII में केंद्र राज्य संबन्धों में वित्तीय संबंधों का वर्णन है। केंद्र, राज्य से वित्तीय मामलों में अधिक मजबूत होने के चलते उसका दायित्व है कि वह राज्यों की आर्थिक मदद करे।

केंद्र द्वारा राज्यों की वित्तीय स्थिति हेतु उपाय

- संवैधानिक उपबंधों की पूर्ति
  - विवेकानुदान द्वारा
  - कार्यकारी अनुदान
- राज्यों को केंद्रीय सहायता
  - स्पेशल राज्य का दर्जा देना
  - केंद्रीय योजनाओं में राज्यों का हिस्सेदार करना (उदा० PDS, आयुष्मान)
- कर, राजस्व सुधार करके
  - GST सुधार
  - GST compensesion
- राजकोषीय प्रबंधन (GSDP का 3% ऋण, तथा प्रभावी सुधारों पर 0.5% अतिरिक्त ऋण)
- राज्यों में प्रभावी विद्युत सुधार
  - मीटरिंग व्यवस्था
  - विद्युत वितरण (वितरण कंपनियों का सुधार)

2364
VISION IAS™

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

राज्य सरकारों की चुनौतियां -

1) सीमित राजस्व आधार
2) केंद्र पर अधिक निर्भरता
3). राज्यों में प्रभावी, करसुधार विद्युत सुधारों को लागू न करना
4). राज्यों के पास सीमित संसाधन
5). क्षेत्रीय विकास में असंतुलन

अन्य कारक
- Freebeis Politics का बढ़ता प्रचलन
- राजकोषीय सुधार प्रबंधन को प्रभावी रूप से लागू न करना
- (आर्थिक सर्वेक्षण 2023 - राज्यों का ऋण भार बढ़ा है
- ज्यादा ऋण लेने से बढ़ता ब्याज भार
- GST Compensesion का न मिलना (अभी तक 60% राज्यों मिला है)

~~आगे भी~~,

अतः राज्यों की अपनी चुनौतियां है फिर भी केंद्र के पास अधिक संसाधन तथा वित्तीय क्षमता होने के नाते, राज्यों की मदद करते हुए उन्हें अनुदान देने चाहिए।

2364

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Q5. हाल ही में भारत के उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के विरुद्ध अधिकार जीवन और समानता के अधिकार से संबद्ध है। पर्यावरण संबंधी मुद्दों के संवैधानीकरण में न्यायपालिका द्वारा निभाई गई भूमिका पर चर्चा कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

The Supreme Court of India recently recognised that the right against the adverse impacts of climate change is intertwined with the right to life and equality. Discuss the role played by the judiciary in constitutionalization of environmental issues. (Answer in 150 words) 10

भारत का संविधान अनुच्छेद 21 में वर्णित जीवन के अधिकार को मानवीय गरिमा के साथ जीने के रूप में परिभाषित करता है। जलवायु परिवर्तन के दौर में सुप्रीम कोर्ट ने जीवन के अधिकार दायरे का विस्तार किया है।

SC द्वारा Art 21 का विस्तार →
- स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार
- स्वच्छ वायु का अधिकार
- स्वच्छ जल का अधिकार
- बेहतर स्वास्थ्य का अधिकार
- प्रदूषण मुक्त जीवन का अधिकार

पर्यावरणीय मुद्दों के संवैधानिकरण में SC की भूमिका।

1) दिल्ली जलबोर्ड Vs पीपल्स ऑफ इंडिया वाद में सुप्रीम कोर्ट ने स्वच्छ व सतत् जलापूर्ति को जीवन का अधिकार माना है।

2). NGT vs दिल्ली सरकार वाद में सुप्रीम कोर्ट ने स्वच्छ हवा को जीवन का अधिकार माना।

3) दिल्ली में पटाखों का बैन लगाना।

सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का प्रभाव

→ NGT अधिनियम की स्थापना 2010

→ NCR में प्रदूषण से निपटने हेतु ~~NCR~~ प्रदूषण आयोग का गठन 2020 में किया गया।

→ पर्यावरण ~~प्रदूषण~~ संरक्षण अधिनियम (1986)

→ ऊर्जा विद्युत अधिनियम (2002)

— वन अधिनियम (1988)

अतः जीवन का अधिकार, पर्यावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध स्वस्थ जीवन में ~~संरक्षण~~ जीने के लिए SC को विधिक कार्रवाई करने हेतु प्रेरित करता है। SC ने विभिन्न पर्यावरणीय वादों में Art 21 का विस्तार किया है ताकि लोगों का गरिमापूर्ण जीवन जलवायुपरिवर्तन के प्रभावों से प्रभावित नहीं हो।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Q6. स्वयं सहायता समूहों (SHG) के संघ भारत में SHGs को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण संस्थागत नवाचार के रूप में उभरे हैं। विवेचना कीजिए। इनके कामकाज को कौन-सी कमियां बाधित करती हैं? (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

SHG federations have emerged as an important institutional innovation to sustain SHGs in India. Discuss. What inadequacies hamper their functioning? (Answer in 150 words) 10

SHG. विशेष समूहों जिनकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि समान है, को एक नाव जुड़कर कार्य करने हेतु प्रेरित करते हैं। सूक्ष्मवित्त की उपलब्धता से SHG भारत में सामाजिक-आर्थिक कल्याण में परिवर्तन कारी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। उदा-कुटुम्बश्री

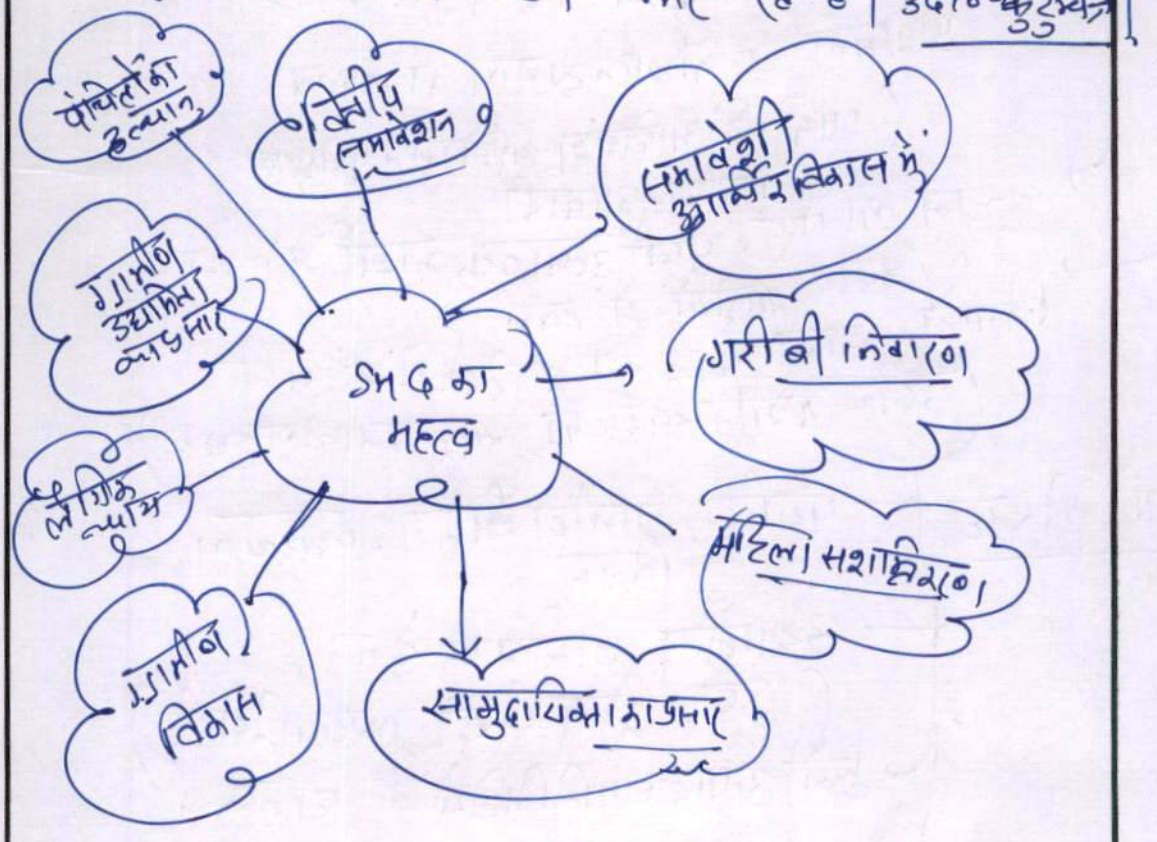

2364
VISION IAS™

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

हालांकि अपनी बहुआयामी आवश्यकता के बावजूद SHG विभिन्न बाधाओं का सामना कर रहे हैं।

बाधाएं:

- ऋणों तक कम पहुंच (SHGs को ऋण देने वाले संस्थान शहरों में संकेंद्रित हैं तथा वाणिज्यिक बैंकों पर निर्भर हैं।)
- बैंकिंग अवसंरचना का ग्रामीण इत्यादि क्षेत्रों में कम पहुंच (70% बैंकों शहरी क्षेत्रों में)
- ऋणों पर उच्च ब्याज (कई माइक्रोफाइनेंस संस्थान 26% तक ब्याज वसूली करते हैं।)
- प्रशिक्षण व कौशल क्षमता का अभाव (SHG में अधिकांश अशिक्षित व अकुशल ग्रामीण आबादी)
- धन का गैर-पूंजी उत्पादक कार्यों में व्यय (उदा० शादियों में खर्च)
- विभागों द्वारा धन का इतरक्षेत्रों में व्यय (उदा० मशीन खरीदना, साहूकार ऋण चुकाना)

आगे की राह

- पर्याप्त, ग्रामीण बैंकिंग अवसंरचना विकास
- उद्यमिता प्रशिक्षण देना (उदा० ड्रोन दीदी, लखपति दीदी)
- पूंजी उत्पादक गतिविधियों में धन खर्च
- निम्न ब्याज।

अतः SHGs ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने तथा सधारणीय व समावेशी विकास हेतु महत्वपूर्ण है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

Q7. बार-बार स्थानांतरण भारत में उच्चतर सिविल सेवा की एक गंभीर समस्या है। सिविल सेवकों के बार-बार स्थानांतरण से जुड़े दोषों पर चर्चा कीजिए और इस समस्या के समाधान के लिए सुधारों का सुझाव दीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

Frequent transfers are a pervasive problem among the higher civil service in India. Discuss the drawbacks associated with frequent transfers of civil servants and suggest reforms to overcome this issue. (Answer in 150 words) 10

भारत में सिविल सेवाओं का विकास औपनिवेशिक विरासत के साथ हुआ था आजादी पश्चात इसे विकास के स्टीलफ्रेम के रूप में देखा गया ~~था~~। हालांकि विभिन्न राजनैतिक गतिविधियों व हस्तक्षेप से इनकी प्रभावशीलता कमजोर हुई है

बार - बार स्थानांतरण क्यों :-

1). राजनैतिक दबाव
(उदा० अशोक खेमका (IAS) 52 बार ट्रांसफर ( ))
2) सामाजिक परिस्थितियां
(उदा० सांप्रदायिक प्रभावित क्षेत्रों में तथा नक्सल क्षेत्रों में
3). प्रभावी निर्णयन व क्रियान्वयन क्षमता का अभाव
4). राजनेताओं द्वारा सत्ता परिवर्तन होते ही अपने मनपसंद अधिकारियों को तर्जीह देना

स्थानांतरण से जुड़े दोष

1) भ्रष्टाचार को बढ़ावा

(वोहरा समिति)

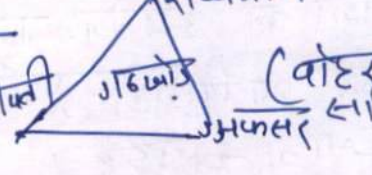

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

2) ईमानदार अधिकारियों का प्रदर्शन क्षमता कम होना
(उदा० IAS अनिल स्वरूप द्वारा कोयला आवंटन सुधारों को उनके स्थानांतरण बाद भ्रष्टाचार से नहीं बचाया जा सका)

3). अधिकारियों में नकारात्मक मनोवृत्ति का विकास तथा मोटिवेशन कम होना

4) यथास्थिति वाद को बढ़ावा

5). विकास कार्यों पर विपरीत प्रभाव
- धन का दुरुपयोग करके
- परियोजनाओं का लम्बीकरण व विलम्ब

समाधान
- 2nd ARC की सिफारिशें लागू करना
(उदा० उच्च अधिकारियों की हस्तांतरण हेतु एक अलग प्रशासनिक आयोग का गठन)
- पुलिस अधिकारियों का स्थानांतरण राज्य आयोग व संघ लोक सेवा आयोग द्वारा
(उदा० DGP से ऊपर रैंक वालों का 2 – 3 वर्ष का स्थायी निश्चित कार्यकाल
- सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का पालन करना

अतः भारतीय सिविल सेवा लोकतंत्र के लाभों को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के उपकरण है। इनके कार्यविधि में अनावश्यक हस्तक्षेप रोका जाना चाहिए।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

Q8. प्रमुख खाद्य उत्पादक होने और व्यापक पोषण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के बावजूद, भारत कुपोषण के संकट से क्यों जूझ रहा है? (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

Despite being a major food producer and implementing extensive nutrition programmes, why does India continue to struggle with the malnutrition crisis? (Answer in 150 words) 10

NHFS-5 का सर्वेक्षण भारत में गंभीर कुपोषण को उजागर करता है (NHFS-5, 37% Child wasting, 47% Child stunting है) है। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक 111/125 देशों में गंभीर स्थिति को उजागर करती है)

भारत कुपोषण संकट के कारण

1) चरम निर्धनता खाद्यान्न तक पहुंच सीमित करती है (नीति Niti आयोग MPI रिपोर्ट में 21.5 करोड़ लोग गरीब)

2) खाद्य मुद्रास्फीति का बढ़ना
उच्च खाद्य मुद्रास्फीति लोगों की पोषण युक्त भोजन पहुंच को सीमित करती

3). PDS उपायों की सीमितता
- अपौष्टिक व खराब गुणवत्ता युक्त खाद्यान्न वितरण

4). खाद्यान्न उपभोग प्रतिरूप में बदलाव
- मुख्यतः खाने में अनाज
- दाल, श्रीअन्न, अण्डे की कमी

5) जंक फूड का बढ़ता प्रचलन
- Child obesity
- Over wasting.

6) मिड डे मील में सीमित खाद्य विविधता
- छिपी भूख (का बढ़ना)

7) सरकारी योजनाओं की विफलता
- लीकेज, भ्रष्टाचार, कालाबाजारी (PDS)
- One size fit for all approach

समाधान

- खाद्य मुद्रास्फीति पर लगाम लगाना
- खाद्यान्न विविधता बढ़ाना (फल, अंडा, मछली को बढ़ावा)
- श्री अन्न, मिलेट्स को PDS में शामिल करना
- सरकारी योजनाओं की निगरानी व Social Auditing
- मिड डे मील के तहत, अंडा, केला तथा दूध, घी का वितरण
- किसानों को अनाज (गेहूं, चावल) के अतिरिक्त बागानी, मत्स्य उत्पादन, दाल उत्पादन हेतु प्रोत्साहन देना
- गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ना
  - DBT तथा न्यूनतम मजदूरी से, निर्वाह मजदूरी

अतः विकसित भारत (2047) लक्ष्य प्राप्ति हेतु स्वास्थ्य मानव पूंजी का निर्माण आवश्यक है।

Q9. "ईरान के साथ भारत के घनिष्ठ संबंध जारी रहेंगे, भले ही इससे पश्चिम को असुविधा हो।" उपर्युक्त कथन के आलोक में, स्पष्ट कीजिए कि ईरान के साथ संबंध जारी रखना भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

"India's close engagements with Iran would continue even if it may cause discomfort with the West." In the light of the above statement, explain why maintaining a relationship with Iran is significant for India. (Answer in 150 words) 10

"ईरान के साथ भारत के संबंध सभ्यता व सांस्कृतिक प्रगाढ़ता तथा आर्थिक, ऊर्जा जरूरतों के जुड़ाव से आकार लेते हैं।"
(विदेश मंत्रालय)

भारत तथा ईरान के संबंध दो सभ्यताओं के मिलन को दर्शाते हैं।

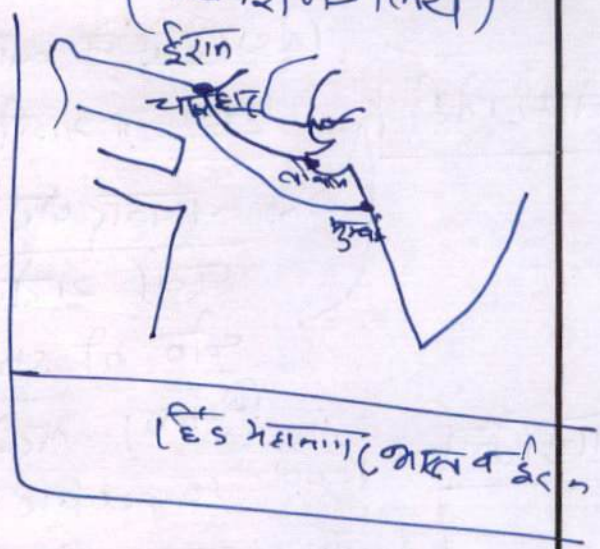

eg. → इंडस घाटी सभ्यता तथा मेसोपोटामियन सभ्यता

मध्यकाल में फारसी तथा मुगल साम्राज्य के बीच व्यापक संबंध।

भारत के ईरान के साथ संबंध महत्वपूर्ण हैं:

आर्थिक → ईरान भारत का ऊर्जा सुरक्षा तथा कच्चे तेल की रणनीति से बड़ा भागीदार है
→ ईरान से भारतीय प्रवासियों द्वारा रेमिटेंस भेजना

2364
VISION IAS™
Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

भू रणनीतिक
1. (रूस - ईरान - चीन - पाक) धुरी को रोकने तथा सन्तुलित करने हेतु
2. चाबहार बंदरगाह द्वारा पाकिस्तान पर निगरानी
3. अफगानिस्तान तथा ईरान के रास्ते ~~मध्य~~ यूरोप से जुड़ाव

सुरक्षा
- फारस की खाड़ी से होने वाले व्यापार की सुरक्षा हेतु
- युद्धाभ्यास (अल-जबर)
- अरब सागर तथा लाल सागर में हूती विद्रोहियों से व्यापारिक जहाज सुरक्षा

कनेक्टिविटी
- IMEC का भागीदार
- चाबहार पोर्ट द्वारा मध्य एशिया तथा पूर्वी यूरोप तक पहुंच
- चीन की String of Pearls को नियंत्रण करने हेतु

सांस्कृतिक
- People to people connection
- सभ्यतागत संबंध
(उदा० भारत ने फारसी को 8वीं संवैधानिक अनुसूची में शामिल किया है)

अतः भारत-ईरान संबंध अमेरिकी प्रभाव तथा रूस-यूक्रेन युद्ध के चलते व इजराइल संघर्ष को पश्चिम द्वारा समर्थन दिये जाने से आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है किंतु हमारे संबंध सभ्यता की जड़ों से जुड़े हैं।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Q10. भारत और चीन के बीच सीमा तनाव को प्रभावी तरीके से कम करने में भारत-चीन सीमा शांति और स्थिरता समझौते (BPTA) की भूमिका पर चर्चा कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

Discuss the role of the India-China Border Peace and Tranquility Agreement (BPTA) in effectively diffusing border tensions between India and China. (Answer in 150 words) 10

भारत और चीन के बीच विस्तृत सीमा है। जिसके चलते सीमा संबंधों में तनाव बना रहता है उदा० ~~गल~~ गलवान हिंसा, तथा डोकलाम विवाद हाल की घटनाएं हैं। इनसे निपटने हेतु दोनों देशों ने BPTA समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं।

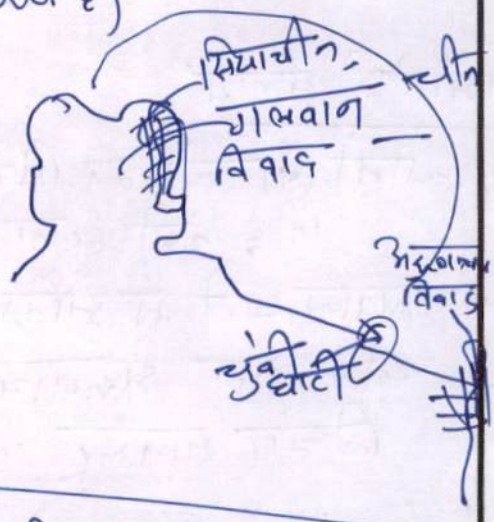

भारत और चीन के बीच विवाद काफी पुराने हैं

कारण ① मैकमोहन रेखा का अस्पष्ट विभाजन तथा चीन द्वारा इसे नहीं मानना

fig- भारत-चीन विवादित क्षेत्र

② चीन का तिब्बती विस्तार तथा वर्तमान की विस्तारवादी नीति विवादों को बढ़ा रही है
(उदा० ~~उत्त~~ अरुणाचल में चीन द्वारा भारतीय सीमा के अंदर गांव बसाना

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

सीमा विवाद कम करने हेतु BPTA की भूमिका -

→ दोनों देशों के उच्च राजनयिक अधिकारी किसी भी विवाद पर मिलकर बात करेंगे
→ विवादित क्षेत्रों का स्पष्ट सीमांकन किया जाना
→ नये विवादों को रोकना
→ विवादित क्षेत्रों से सेनाओं को पीछे हटाना
→ आर्थिक सहयोग बढ़ाना
– सांस्कृतिक संबन्ध मजबूत करना

समझौते की सीमायें

→ चीनी सैनिकों का विवादित क्षेत्र से पीछे नहीं हटना
→ गलवान घाटी का अतिक्रमण
→ चीन द्वारा अरुणाचल को मैकमोहन का पूर्वी विस्तार मानकर अपना कब्जा बताना

अतः भारत - चीन सीमा विवाद औपनिवेशिक विरासत तथा चीनी विस्तार का परिणाम है। जिसे शांति समझौतों तथा व्यापक आर्थिक भागीदारी द्वारा दूर किया जा सकता है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

Q11. आपकी राय में, लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के लिए एक साथ निर्वाचन कराने से भारत में समग्र शासन को किस हद तक बढ़ावा मिल सकता है? (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

To what extent, in your opinion, can holding simultaneous elections to the Lok Sabha and State Legislative Assemblies augment overall governance in India? (Answer in 250 words) 15

हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति द्वारा 'एक राष्ट्र एक चुनाव' पर विस्तृत रिपोर्ट संसद को सौंपी गई है। जिससे एक राष्ट्र एक चुनाव का मुद्दा फिर बहस की वीथि में है।

एक राष्ट्र एक चुनाव :

- लोकसभा व राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराना
- 270 वीं विधि आयोग की रिपोर्ट ने भी इसका समर्थन किया था
- एक साथ चुनाव कराने का आशय एक ही दिन चुनाव कराना नहीं

लोकसभा व राज्यविधानसभा चुनाव एक साथ कराने से शासन को लाभ :

1) चुनावी व्यय तथा सार्वजनिक बोझ को कम करेगा (उदा० हाल ही में 18वीं लोकसभा चुनाव में 5000 करोड़ का खर्च)

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

2) सरकारी मशीनरी को विकासात्मक कार्यों में भाग लेने का अधिक समय मिलेगा
(उदा० सरकारी शिक्षकों का बार-बार चुनावों में उपयोग उनकी दक्षता को कम करता है) एक साथ चुनाव इसे दूर करेगा।

3). आचार संहिता लगाने से विकास कार्यों में आने वाली बाधाओं का समाधान

4). पुलिस तथा अन्य प्रशासनिक मशीनरी नागरिक कल्याण पर ध्यान देगी

5). बार-बार चुनाव होने से राजनीतिक व्यय बढ़ने से भ्रष्टाचार बढ़ने पर लगाम लगेगी

6). दीर्घकालिक नीतियों का निर्माण तथा प्रभावी क्रियान्वयन

एक साथ चुनाव कराने की चुनौतियां

- संवैधानिक - कई राज्य विधानसभाओं को भंग किया जा सकता है तथा राष्ट्रपति शासन का प्रयोग व संवैधानिक संशोधन करना पड़ सकता है
- प्रशासनिक - इतने विशाल देश में चुनाव सम्पन्न कराने हेतु अधिक मानव संसाधन की जरूरत पड़ेगी

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

एक साथ चुनावों की सीमायें व आलोचनायें :

- राजनीतिक उत्तरदायित्व व जवाबदेहिता को कम करेगा (राजनेता – जनता के बीच 5 साल में 1 बार)
- भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे सकता है
- क्षेत्रीय मुद्दों की अनदेखी
- केंद्र का राज्यों पर प्रभुत्व, जिससे संघवाद प्रभावित

आगे की राह:
- क्रमिक रूप से एक साथ चुनाव की ओर बढ़ना
  जैसे - पंचायतों व नगरपालिकाओं के एक साथ
- हाइब्रिड चुनावों की ओर बढ़ना (FPTP तथा आनुपातिक चुनावी पद्धति)

अतः सुशासन की प्राप्ति तथा देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में चुनावी प्रणाली महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लोकतंत्र के विकास को अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने हेतु न सिर्फ एक साथ चुनाव बल्कि राजनीतिक उत्तरदायीत्व तथा जवाबदेहिता को प्राथमिकता देना चाहिए।

2364

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Q12. भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है जो समाज की बदलती आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करने के लिए समय के साथ विकसित हुआ है। टिप्पणी कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

The Indian Constitution is a living document that has evolved with time to reflect the changing needs and aspirations of the society. Comment. (Answer in 250 words) 15

डा० अम्बेड्कर ने 'संविधान सभा के समक्ष वक्तव्य दिया था कि भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। जो सामाजिक जरूरतों तथा लोगों की महत्वकांक्षाओं की पूर्ति हेतु स्वयं को बदलने का प्रावधान करता है) संविधान का लचीलापन इसे जीवंत बनाता है)

{सामाजिक आकांक्षाओं तथा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संविधान का विकसित स्वरूप}

(1) राष्ट्रीय एकता अखण्डता, तथा साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखने हेतु 42 वां संविधान संशोधन
(प्रस्तावना में एकता, अखण्डता पंथनिरपेक्षता शब्द जोड़ा जाना)

(2) मौलिक अधिकारों का व्यापक विस्तार

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

उदा० 86 वां संविधान संशोधन, शिक्षा का अधिकार (2009),

3). देश में नागरिकों के जीवन को गुणवत्ता पूर्ण तथा गरिमामय बनाने हेतु - अनुच्छेद - 21 का विस्तार

(उदा० → स्वास्थ्य का अधिकार
→ पर्यावरण का अधिकार
→ विवाह करने का अधिकार (हादिया वाद 2017)
→ निजता का अधिकार
पुट्टास्वामी वाद (2017)
→ विवाह व तलाक का अधिकारों की व्याख्या
तीन तलाक वाद (2018)

4). राज्य के कर्तव्यों को बढ़ाने तथा सामाजिक-आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देने हेतु DPSP में संशोधन

(उदा० → 44 वां संशोधन - Art 38(2)
→ न्याय तक पहुंच हेतु - 39(A)
→ NALSA का गठन (1987)
पर्यावरण संरक्षण हेतु - 48(A) का प्रावधान

5). युवाओं को चुनावी भागीदारी में लाने हेतु
उदा० 61 वां संविधान संशोधन
मतदान आयु 21 से 18 वर्ष

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(6) सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण तथा ग्रामीण विकास हेतु, शक्ति का विकेंद्रीकरण

उदा० 73 वां व 74 वां संविधान संशोधन (1992)

↳ विकास प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी तय हुई तथा विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे

(7). सामाजिक न्याय हेतु

(OBC आरक्षण
EWS आरक्षण)

अतः भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता उसकी जीवंतता है जो समाज की महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति में अनुरूप स्वयं को अनुकूलित करती है

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Q13. भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में विद्यमान कमियां विचाराधीन कैदियों के मानवाधिकारों को किस प्रकार प्रभावित करती हैं? इन कमियों को दूर करने के लिए कौन-से सुधार आवश्यक हैं? (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

How do the deficiencies in the Indian criminal justice system impact the human rights of undertrial prisoners? What reforms are necessary to address these deficiencies? (Answer in 250 words) 15

भारत के मानवाधिकार संगठनों तथा कार्यकर्ताओं ने आपराधिक न्याय प्रणाली की आलोचना करते हुए इसमें व्यापक बदलावों की मांग की है। इस दिशा में सरकार ने भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय दण्ड संहिता तथा भारतीय साक्ष्य एक्ट 2023 पारित किये हैं।

भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली की कमियां तथा विचाराधीन कैदियों पर प्रभाव

1). भारत की जेलों में 80% से ज्यादा कैदी ऐसे हैं जो या तो विचाराधीन हैं या जिनको सजा मिल चुकी है, वे अपनी सजा के समय से ज्यादा ~~काट~~ काट रहे हैं। (NCRB-2022)

2) गृहमंत्रालय में विचाराधीन कैदियों की समस्या का प्रमुख कारण औपनिवेशिक कानूनों को माना है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

3). न्यायपालिका पर अत्याधिक बोझ
(22वें विधि आयोग के अनुसार देशभर में 3.4 करोड़ केस लम्बित हैं)

4). अपराधियों के साथ अमानवीय व्यवहार

5) जेलों में क्षमता से अधिक लोग

6). महिला जेलों की अधिक से ज्यादा नहीं
(↳ महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा)

7). विचाराधीन कैदियों के मानवाधिकारों का उल्लंघन
(उदा. → जेलों में उत्पीड़न, मारपीट, हिंसा
↳ Custodial death का बढ़ना)

सुधार

- गृह मंत्रालय ने आपराधिक न्यायसंहिता 2023 संसद पारित किया है
- गृहमंत्रालय ने अपराध पहचान हेतु NATGRID प्रणाली को अपनाया जाना
- फास्टट्रैक कोर्ट की स्थापना करना
- दण्ड द्वारा निर्धारित समय से ज्यादा सजा काट चुके कैदियों को रिहा करना

- विचाराधीन कैदियों के मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य की व्यवस्था करना
- अपराध से अधिक सजा काट चुके कैदियों को क्षतिपूर्ति देना

आगे की राह
- NPTGRID तथा फेशियल रिकॉग्निशन व AI जैसी तकनीकों का प्रयोग करना
- कोर्ट आदेशों के त्वरित चालान हेतु FASTER प्रणाली का प्रभावी उपयोग
- जेल सुधार नियम 2023 को लागू करना
- फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापना
- न्यायधीशों की भर्ती करके रिक्त स्थानों को भरना

अतः न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए होते हुए दिखना भी चाहिए। गांधी के शब्दों में 100 दोषी छूट जाएं पर एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। विचाराधीन कैदियों के साथ मानव आचरण युक्त व्यवहार करते हुए उन्हें त्वरित सुनवाई कर समाधान देना चाहिए।

2364

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Q14. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) भारत में मानवाधिकारों के प्रहरी के रूप में अपनी भूमिका का प्रभावी तरीके से निर्वहन क्यों नहीं कर पाया है? इसे ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टिट्यूशंस (GANHRI) से मान्यता प्राप्त करने से रोकने के लिए कौन-से कारण उत्तरदायी हैं? (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

Why has the National Human Rights Commission (NHRC) not been able to effectively carry out its role as the watchdog of human rights in India? What are the reasons that have prevented it from getting accreditation from the Global Alliance of National Human Rights Institutions (GANHRI)? (Answer in 250 words) 15

मानव अधिकारों के संरक्षण व सुरक्षा हेतु 1993 में मानवअधिकार आयोग का गठन सांविधिक (statutory) आयोग की तर्ज पर किया गया था। आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है।

NHRC की भूमिका व कार्य

- मानवाधिकारों को प्रभावित करने वाले नियम कानूनों की निगरानी
- केंद्र व राज्य सरकार की मानवाधिकारों को प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर नजर रखना
- प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन करते हुए अपने सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समन करना, जेलों का निरीक्षण करना, कारखानों में श्रमिकों की हालत का जायजा लेना आदि।

प्रभावी भूमिका का निर्वहन क्यों नहीं ?

1) अध्यकारी नियुक्ति की शक्तियों का अभाव
(उदा० राज्य सरकारें मानव अधिकार आयोग की सिफारिशों का उल्लंघन करती हैं)

2) आयोग में विधि विशेषज्ञों तथा बहुआयामी मानवीय दृष्टिकोण वाले सदस्यों का अभाव
(उदा० NHRC रिटायर्ड नौकरशाहों तथा पूर्वजजों का मंच बन गया है)

3) NHRC 7 वर्ष पूर्व उल्लंघन के मामलों की जांच व देख रेख नहीं करता है

4) विभिन्न आयोगों के समन्वय का अभाव

5) जांच व अन्वेषण हेतु संसाधनों तथा मानवशक्ति व कौशल का अभाव

6) NHRC में बढ़ता राजनैतिक हस्तक्षेप
(उदा० मणिपुर मामले पर चुप्पी)

(GANHRI) से NHRC को मान्यता खोने के कारण :-

(7) NHRC में बढ़ता राजनैतिक हस्तक्षेप
(उदा० CAA(NRC) आंदोलन में मानवाधिकारों के हनन पर चुप्पी)

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

2) कृषक तथा श्रमिक व वंचित लोगों के अधिकार उल्लंघन पर व्यापक चुप्पी
(उदा० कृषक आंदोलन में NHRC की निष्क्रियता)
→ वंचितों पर बढ़ते अत्याचारों पर चुप्पी
(उदा० सोनभद्र में आदिवासियों के खिलाफ हिंसा)

3). मणिपुर हिंसा में मानवाधिकार के मुद्दों को प्रभावी रूप ले न उठाना

4). महिलाओं के खिलाफ हिंसा यौन अत्याचार को राज्य सरकारों की जवाबदेही पर चुप्पी

5). NCRB रिपोर्ट, जेलों की अमानवीय दशा तथा बढ़ती custodial death पर NHRC की प्रभावी कार्रवाई नहीं

6). वैश्विक मानवाधिकार उल्लंघनों पर अपना वक्तव्य नहीं देना
(उदा० इजराइल-फिलिस्तीन युद्ध, युक्रेन युद्ध, पर्यावरणीय शरणार्थी)

आगे की राह
- NHRC को कानूनी शक्तियां देना
- बाध्यकारी निर्णय के प्रावधान
→ NHRC की मानवसंसाधन क्षमता बढ़ाना तथा उसके अपने कर्मचारियों का प्रावधान करना

अतः मानवाधिकारों को संरक्षित करने के लिए NHRC की भूमिका प्रभावी है

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Q15. महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतिशोध) अधिनियम, 2013 की पृष्ठभूमि और प्रमुख प्रावधानों पर चर्चा कीजिए। अधिनियम के कार्यान्वयन में सामना की जाने वाली चुनौतियों को सूचीबद्ध कीजिए। इसकी प्रभावशीलता को बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? इस संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का संदर्भ प्रस्तुत कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

Discuss the background and key provisions of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013. List the implementation challenges that the Act faces. What measures can improve its effectiveness? Refer to Supreme Court judgments in this regard. (Answer in 250 words) 15

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

VISION IAS™

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

2364
VISION IAS™

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

Q16. राज्य विधान सभाओं के अध्यक्षों से संबद्ध पूर्वाग्रह और पक्षपात के मुद्दों को देखते हुए, क्या आपको लगता है कि दलबदल विरोधी कानून के तहत उन्हें दी गई शक्तियां वापस ले ली जानी चाहिए? (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

With issues of prejudice and partisanship associated with Speakers of State Legislative Assemblies, should the powers under the anti-defection law be taken away from their hands? (Answer in 250 words) 15

केंद्रीय व्यवस्था की तरह भारत का संविधान, राज्यों की विधानसभा में अध्यक्ष पद का प्रावधान करता है। सभा के प्रभावी संचालन हेतु अध्यक्ष पद को विशिष्ट शक्तियां दी गई हैं।

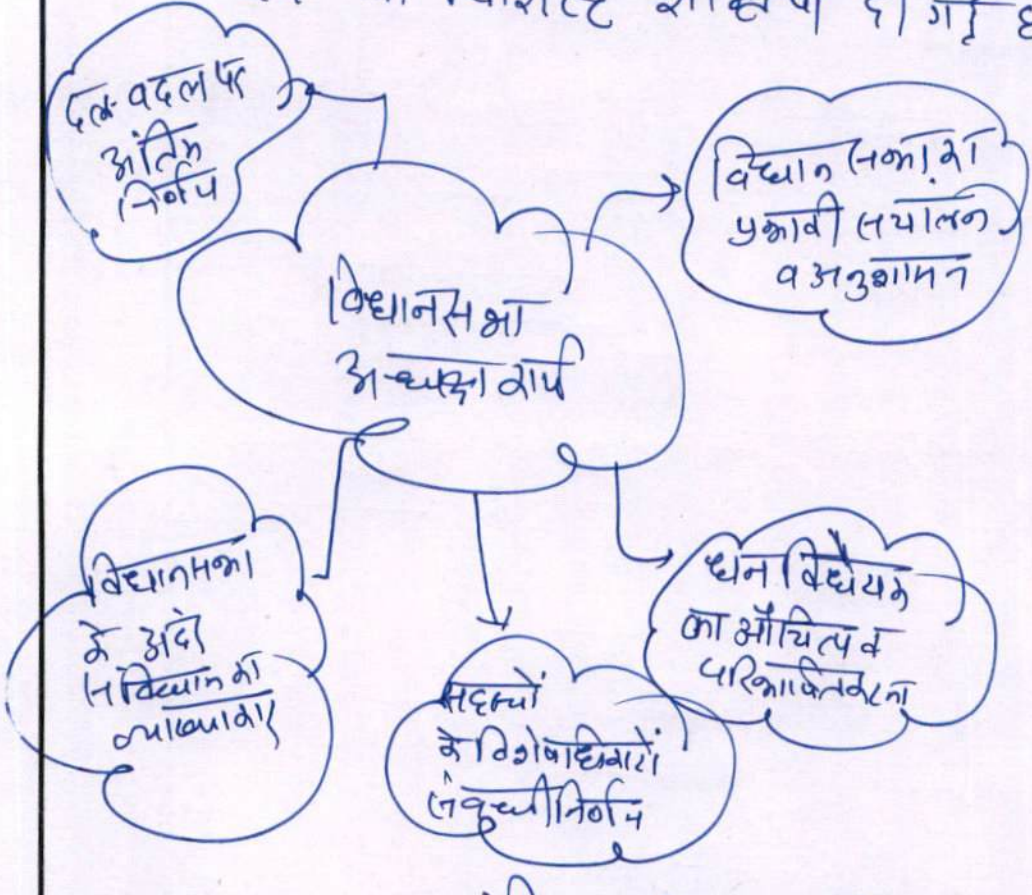

हालांकि उपरोक्त भूमिका व शक्तियां अध्यक्ष को, विधानसभा को निष्पक्ष रूप से संचालित करने हेतु दी गई हैं।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

किंतु अध्यक्ष पद को धारण करने वाले व्यक्ति विभिन्न राजनैतिक दलों से जुड़े होने के कारण इनकी निष्पक्षता पर पूर्वाग्रह हावी रहते हैं।

अध्यक्ष पद पर पूर्वाग्रह व पक्षपात के मुद्दे।

1) दलबदल कानून के तहत प्रभावी कार्यवाही न करना

2). दलबदल के निर्णय को लंबित रखना तथा अंतिम निर्णय न लेना

3). सत्ताधारी दल के हितों के अनुरूप सदस्यों की सदस्यता रद्द करना तथा उन्हें बाहर करना

4). छोटे राजनैतिक दलों के विलय तथा पार्टी टूट को दलबदल के तहत मान्य नहीं करना (उदा. महाराष्ट्र विधानसभा में शिवसेना के दो गुट होना तथा दलबदल पर कठोर कार्यवाई न करना

दलबदल की प्रक्रिया पर निर्णयन को लेकर टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ब्राचिलू vs किहोतोहोलान वाद में अध्यक्ष द्वारा समय पर निर्णय देने को रेखांकित किया गया

2364

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

होलाहान वाद में सुप्रीमकोर्ट ने अध्यक्ष की शक्ति को न्यायिक समीक्षा के अधीन रेखांकित किया।

शक्ति वापस लेनी चाहिए ~~अथवा~~ नहीं

- → अध्यक्ष सदन के भीतर भ्रष्टाचार को कम करके शिष्टाचार बढ़ाता है
- → विधायकों की Horse trading रोकने हेतु अध्यक्ष की शक्ति प्रासंगिक
- → स्थिर सरकार तथा नीतिनिर्माण के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवश्यक
- → भ्रष्ट विधायकों के दल बदल पर रोक लगाने हेतु आवश्यक

आगे की राह

- 170वीं विधि आयोग रिपोर्ट में कि अध्यक्ष को समय से निर्णय लेने का सुझाव
- अध्यक्ष पद को ब्रिटेन की तरह निष्पक्ष बनाने हेतु संबंधित पार्टी से इस्तीफा दे देना चाहिए

अतः भारतीय लोकतंत्र को प्रभावी रूप से संचलन हेतु अध्यक्ष पद को शक्तिशाली बनाया गया है दल बदल पर रोक लगाकर अध्यक्ष अपनी प्रभावी भूमिका निभाता है

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Q17. हाल ही में, यू.जी.सी. ने भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों द्वारा परिसरों की स्थापना और संचालन के लिए विनियम जारी किए हैं। भारत में विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों (FHEIs) के प्रवेश को अनुमति देने के कारणों की विवेचना कीजिए। उनके सुचारू प्रवेश को सुनिश्चित करने में प्रमुख बाधाएं क्या हैं? (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

Recently, the UGC released regulations for establishment and operation of campuses by foreign universities in India. Discuss the reasons for allowing the entry of Foreign Higher Educational Institutions (FHEIs) in India. What are the major obstacles in ensuring their smooth entry? (Answer in 250 words) 15

UGC भारत में उच्चशिक्षा के मानकों, नियमों तथा संचालन गतिविधियों व संस्थाओं को मान्यता देने हेतु प्रमुख संस्थान है। हाल ही में UGC ने उच्चशिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु विदेशी संस्थाओं के प्रवेश की अनुमति दी है।

विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों के प्रवेश की अनुमति दाता —

1) शिक्षा व शोध की गुणवत्ता बढ़ाना
2) ब्रेन ड्रेन (Brain Drain) को रोकना
3) शोध, अनुसंधान में विविधता लाना
4) IPR, पेटेंट को बढ़ावा देना
5) औद्योगिक मांग के अनुरूप शिक्षा को बदलना

5). वैश्वीकृत विश्व में उच्च सामाजिक युक्त मानवपूंजी का विकास करना

6). पश्चिम रोजगार मांग पूर्ति हेतु भारतीय युवाओं को तैयार करना

7) Technology Transfer

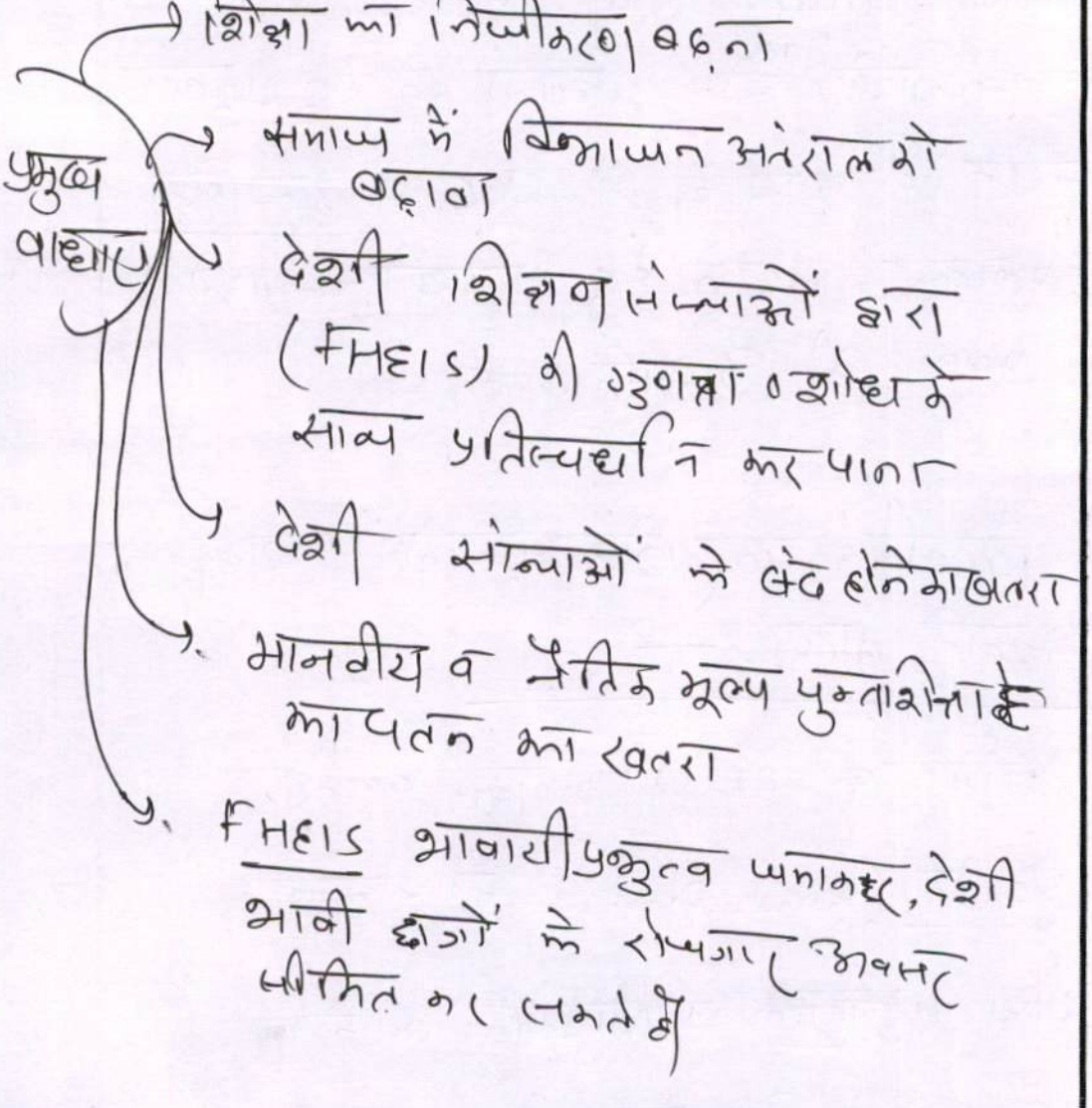

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

समाधान

- शिक्षा पाठ्यक्रम को विविधीकृत बनाना तथा मूल्य आधारित शिक्षा को बढ़ावा
- FHEIs तथा देशी शिक्षण संस्थाओं में Collaboration तथा Joint Research को बढ़ावा देना।

अतः भारतीय उच्च शिक्षा सेक्टर में वास्तविक शोध व गुणवत्तायुक्त शिक्षण हेतु FHEIs के आगमन से नवाचार को बढ़ावा मिलेगा तथा Brain Drain की समस्या का समाधान होगा।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Q18. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) अपने मूल उद्देश्यों को प्राप्त करने में किस हद तक सफल रहा है? (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

To what extent has the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) achieved its core objectives? (Answer in 250 words) 15

DPSP द्वारा राज्यों को दिये गए आधिदेश, अनुच्छेद 42 के तहत प्रत्येक को रोजगार के अवसरों तथा कल्याण कारी राज्य के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु मनरेगा एक प्रभावी उपकरण है

मनरेगा के उद्देश्य
- ग्रामीण विकास को गति देना (उदा० ग्रामीण अवसंरचना निर्माण)
- गरीबी कम करना (विश्व बैंक रिपोर्ट भारत के दो दशकों में 22 करोड़ गरीबी कम की है)
- बेरोजगारी कम करना (प्रत्येक को 100 दिन काम नहीं तो बेरोजगारी भत्ता)
- महिला सशक्तीकरण (30% श्रमिक महिलाएं)
- ग्रामीण पलायन को रोकना (उदा० शहरों पर पलायन दबाव कम हुआ)
- आजीविका व विकास लक्ष्यों की प्राप्ति

उदा० कोविड काल में रोजगार मुहैया कराना तथा ग्रामीण अवसंरचना विकास

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

मनरेगा ~~[illegible]~~ सफल रहा है

1) गरीबी उन्मूलन → विश्वबैंक रिपोर्ट 22 करोड़ लोग दो दशकों में गरीबी से बाहर

2). सार्वजनिक अवसंरचना का विकास
↳ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत प्रत्येक ग्राम जिला मुख्यालयों से जुड़ा

3). महिला सशक्तिकरण
↳ निर्धन व गरीब विधवा महिलाओं को रोजगार प्राथमिकता
↳ जॉब कार्ड व बैंक खाता महिला मुखिया के नाम पर

• मनरेगा की सीमित प्रभाविता
(1) नीति आयोग रिपोर्ट के अनुसार 21.8% करोड़ लोग अभी भी गरीब
(2) ग्रामीण से शहरी ओर पलायन बढ़ा है
(3) निर्धनता दुष्चक्र बना हुआ है
(4) कुपोषण व गरीबी बनी हुई है
(5) ग्रामीण अवसंरचना की कमी

(6) अकुशल श्रमिकों का बढ़ावा

(7). कृषि का स्त्रीकरण → (पुरुषों का शहरी पलायन)

आगे के उपाय
- मनरेगा का बजट बढ़ाया जाना
- → सोशिल आडिटिंग प्रभावी रूप से लागू करना
- → अकुशल कार्यों के साथ-कुशलता युक्त कार्यों को बढ़ावा
- → कौशल विकास पर जोर देना

अतः गांधी के सपनों के ग्रामीण भारत के विकास में मनरेगा सबसे सफल ग्रामीण विकास व रोजगार कार्यक्रम साबित हुआ है बस और अधिक प्रभावी बनाए जाने की जरूरत है

Q19. "बदलती हुई भू-राजनीतिक परिस्थितियां बंगाल की खाड़ी की सामरिक अवस्थिति को हिंद-प्रशांत की व्यापक अवधारणा के लिए महत्वपूर्ण बनाती हैं।" उपर्युक्त कथन के आलोक में, क्षेत्रीय सहयोग और स्थिरता को बढ़ावा देने में बिम्सटेक (BIMSTEC) की भूमिका पर चर्चा कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

"Changing geopolitical realities make the strategic location of the Bay of Bengal crucial to the wider concept of the Indo-Pacific." In the light of the above statement, discuss the role of the BIMSTEC in enhancing regional cooperation and promoting stability. (Answer in 250 words) 15

BIMSTEC की स्थापना 1997 में बंगाल की खाड़ी के देशों के बीच संपर्क, संपार, तथा आर्थिक व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी।

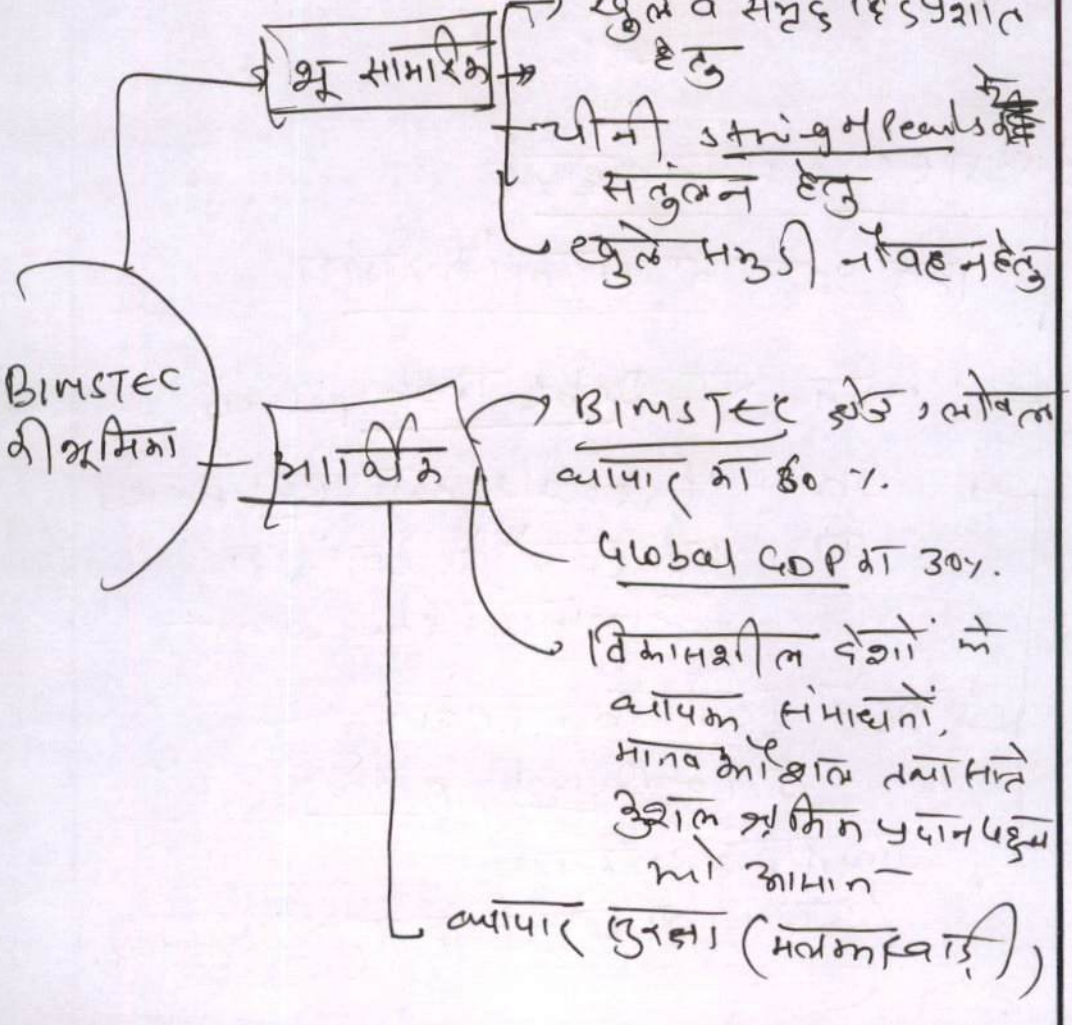

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

भूमिका

→ **सांस्कृतिक** - BIMSTEC क्षेत्र जटिल सामाजिक-सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करते हैं।
→ बुद्ध धर्म का प्रभाव इस क्षेत्र को सांस्कृतिक रूप से जोड़ता है

→ **भू राजनीतिक** - बढ़ते USA तथा यूरोप के बढ़ते आकर्षण इंडो-प्रशांत नीति को आकर्षण का केंद्र बनाता है

BIMSTEC के समक्ष बाधाएं

- हिंद प्रशांत का बढ़ता सैन्यीकरण
- चीन का Debt Trap policy
- String of Pearls तथा BRI project को कई आस-पास के देशों द्वारा स्वीकार्य किया जाना
- बढ़ते कूटनीतिक गठबंधन उदा० Quad, AUKUS
- राजनीतिक अस्थिरता (उदा० बांग्लादेश, म्यांमार में तख्तापलट)

अतः BIMSTEC क्षेत्र में भारत अपनी प्रभावी रणनीतिक स्थिति का फायदा उठाकर, इस संगठन के Potential का लाभ अपने विकास हेतु उठा सकता है

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Q20. विवेचना कीजिए कि भारत की विस्तारित रक्षा कूटनीति किस प्रकार पड़ोस में इसके प्रभाव को सुदृढ़ करती है? (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

Discuss how India's expanding defence diplomacy strengthens its influence in the neighbourhood. (Answer in 250 words) 15

SAGAR पहल तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की रक्षा कूटनीति, उसके क्षेत्रीय प्रभाव को आकार देती है

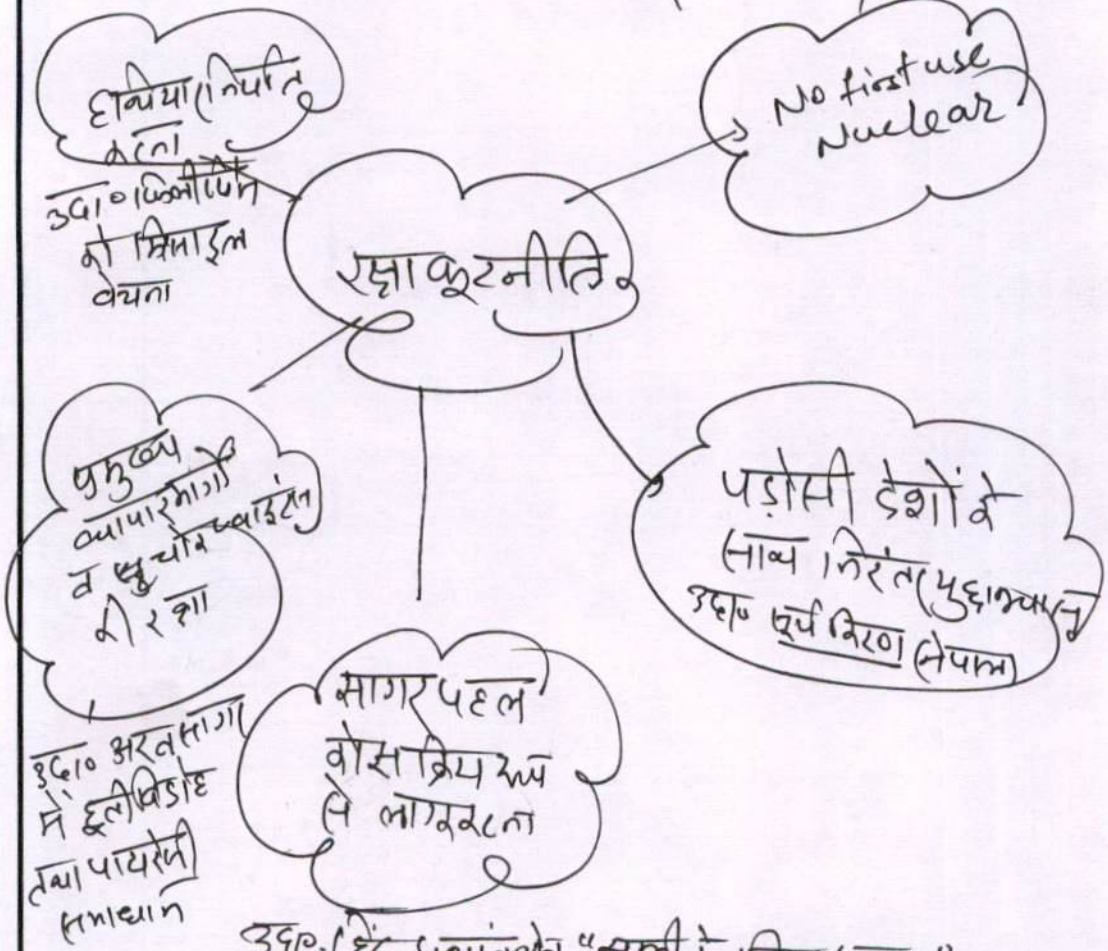

उदा० हिंद प्रशांत क्षेत्र "सभी के लिए सुरक्षा"

भारत अपनी सुरक्षा कूटनीति से अपने पड़ोसियों की ~~प्रभावी~~ रक्षा करने में प्रभावी नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरा है

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

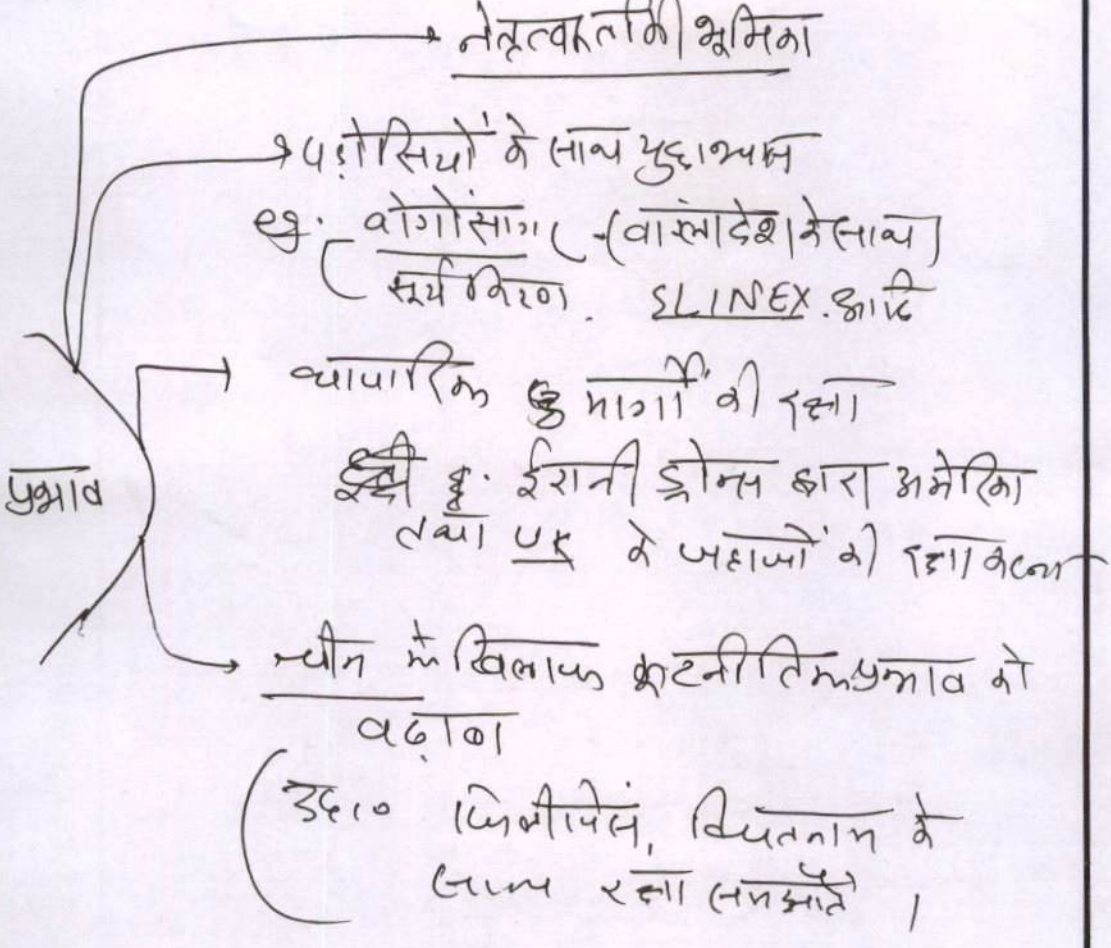

रक्षा कूटनीति की चुनौतियाँ

- भारत की विश्व प्रवर की छवि
- पड़ोसी देशों का चीन के साथ झुकाव
  (उ.दे. श्रीलंका, हंबनटोटा बंदरगाह)
- मालदीव जैसे देशों का Debt trap में फंसना
  (उ.दे. मालदीव में India out मुद्दा)

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)